

प्रेषक,

डॉ० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २४ जनवरी, 2011

विषय:- अंषी सामाजिक एवं शैक्षिक संस्था को ग्राम तौली, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में डी०फार्मा संस्थान की स्थापना हेतु ०.७०२ है० भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-५९६/११-रीडर (२००८-०९), दिनांक-८.१२.२०१० के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, अंषी सामाजिक एवं शैक्षिक संस्था को ग्राम तौली, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में डी०फार्मा संस्थान की स्थापना हेतु ०.७०२ है० भूमि क्य की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(III) के अन्तर्गत, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी अनापत्ति/सहमति एवं आपके द्वारा संस्तुत खाता संख्या-६७ के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1— केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3— केता द्वारा क्य की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-१६७ के परिणाम लागू होंगे।

- 4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकरणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6— शासन द्वारा दी गई भूमि क्य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7— प्रस्तावित भूमि को उपयोग संस्था द्वारा मात्र डी०फार्मा पाठ्यक्रम हेतु ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित भूमि का उपयोग, किसी अन्य कार्य हेतु किये जाने पर, उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में नीहित कर ली जायेगी।
- 8— किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 9— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 10— योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 11— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 12— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ राकेश कुमार)
सचिव।

पृ०प०सं-१६८ / सम्बिनांकित २०१०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

- 4- अध्यक्ष, अंषी सामाजिक एवं शैक्षिक संस्था, रत्नपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।